completed the sowing after the little rains, that has been lost, and now, the poor farmers in this area are in a miserable plight because they do not have money to buy seeds again. Sir, this is a severe situation, and this situation is prevailing not only in Maharashtra, but also in many parts of India. Now, in Maharashtra, the Government is contemplating to have a cloud seeding. It is a good attempt. But I am not very sure whether such experiments really yield any fruit. Therefore, it is a very serious situation. Apart from the farming community, Sir, there is a serious issue of fodder to the cattle-head and also drinking water for the urban and the rural poor. In Mumbai, there have been good rains in the city and suburbs, but the reservoirs which supply water to the metropolis, have not received enough rains, and therefore, there is a problem of the drinking water in this city also.

Sir, I am now talking on a larger canvas of national economy. We are a farming nation and most of the population in this country are farmers, and if rains are delayed like this, the Indian economy is likely to face trouble. Seventeen per cent of the Indian income comes from farming, and Rs. 5.66 lakh crores is the income coming from agriculture. In this situation, I think, the Government needs to take this issue very seriously. This need arises because if the farmers do not get enough and timely help then this kharif crop will go, and if the kharif goes then there would a shortage of foodgrains at the national level and it will have a bouncing impact on everything, on the consumption of goods and the national economy. I, therefore, request, through you, Sir, the Government that this is time to rise and support the farming community. Supply of free seeds and cattle camps is the need of the hour in many areas. I am not pressing the panic button. But if we start this work now, and if there is a calamity, God forbid, and the monsoon is further delayed, then we should not be left with. ...*(Time Bell rings)*. We should not leave the farmers. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Shri Prabhat Jha, please only associate.

SHRI PRABHAT JHA (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Prakash Javadekar.

Acceptance by G-8 plus five countries and India to complete WTO Doha round by 2010

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, मैं कुछ दिनों पहले अमरीका गया था। मेरी वहां के उच्चाधिकारी और वाणिज्य विभाग के उच्चाधिकारियों से बात हुई। तब मुझे एक आशंका हुई कि दोहा राउंड को सफल बनाने के लिए विकसित देश भारत पर दबाव बनाएंगे। इसीलिए 29 तारीख को मैंने एक पत्रकार वार्ता संबोधित करके भारत सरकार को आगाह किया था कि वह दबाव से न झुके। आज जो खबरें इटली से आ रही हैं, जहां प्रधान मंत्री मौजूद हैं और वहां जी-8 प्लस 5 का सम्मेलन हो रहा है, दोहा राउंड को 2010 में पूरा करने के लिए भारत ने मान्यता दी है, इस तरह की खबर आई है। मैं इस विषय पर याद दिलाना चाहता हूं कि यह भारत की बदली हुई भूमिका है। जब अरुण जेटली जी वाणिज्य मंत्री थे तब सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर एक भूमिका कायम हुई थी। वह भूमिका यह थी कि भारत के कृषि हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी और किसान के हित की अनदेखी नहीं होगी। उस समय यह तय किया था कि यह विश्व व्यापार है। हम समान लेवल प्लेयिंग फील्ड के

व्यापार के पक्ष में हैं, लेकिन उसके लिए विकसित देश अपने किसानों को जो बहुत सारी सब्सिडी देते हैं, वह कम होनी चाहिए। यह भूमिका पिछले पांच साल सरकार ने भी जारी रखी थी। आज लगता है कि चुनाव के बाद माहौल अचानक बदल गया है। चुनाव के बाद सारा माहौल बदला-बदला नजर आया है। मंत्री भी बदले हैं और पॉलिसी भी बदली गई है। उन्होंने अमरीका में एक महीने पहले जाकर ऐलान किया कि अमरीका और भारत की इस विषय में अब कोई दो राय नहीं है, उनकी कोई अलग-अलग राय नहीं है। परंतु हमारी राय अलग-अलग है। आज जो खबर आई है, यह भारत की कृषि के लिए खतरे की घंटी बजी है। विकसित देश सब्सिडी तो डायरेक्ट देते ही हैं, साथ ही ग्रामीण परिवेश कायम रखने के नाम पर और सब्सिडी दे रहे हैं। वे जो भारत के कहने पर, विकासशील देशों के कहने पर, लिव इट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उस समय एक यूनियन बनाई थी और सब मिलकर लड़े थे, इसलिए दोहा राउंड पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब जो हो रहा है, भारत का किसान उससे कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। वह कभी भी उससे प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां उसे लागत मूल्य पर आधारित कीमत भी नहीं मिल रही है। हम समान स्पर्द्धा के लिए तैयार हैं। हम विश्व व्यापार के लिए तैयार हैं, लेकिन यह विश्व व्यापार भारत की खेती को ले डूबेगा। यह किसान को मृत्यु दंड देगा, उसके लिए आत्महत्या के सिवाय कोई राह नहीं रहेगी। इसलिए सरकार अभी जाग जाए। हम चेतावनी देते हैं कि आप यह स्टैंड बदलें। जो स्टैण्ड पहले से है, आप वही रखिए, नहीं तो संघर्ष होगा। यह संघर्ष सदन में भी होगा और बाहर भी होगा।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra) : Sir, I associate myself with the issue raised by Shri Prakash Javadekar.

श्री ओ.टी. लेपचा (सिक्किम) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करता हूं।

Circulation of fake currency notes in the country

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नकली करेंसी नोट्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, पहले बच्चों को लुभाने के लिए चूरन के साथ नकली नोट मिला करते थे, पर अब एक देश की अर्थनीतिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हमारे पड़ोसी देश नकली नोटों का प्रचलन चला रहे हैं। पहले पचास रुपए का नकली नोट बनाया गया, उसके बाद सौ रुपए का, पांच सौ रुपए और हजार रुपए बनाया गया है। पहले घुसपैठिए अपने साथ नकली नोट लाते थे। जब वे पकड़े जाते थे, तो जेल जाते थे या कार्रवाई होती थी या seize कर लिए जाते थे। दुर्भाग्य यह है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ट्रेजरी से भी नकली नोट निकल रहे हैं। पिछले दिनों हमने डुमरियागंज में देखा ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूं, डुमरियागंज में एसबीआई की ट्रेजरी से नकली नोट मिले और करोड़ों की संख्या में मिले। जहां एटीम vending machine लगाई गई है, जहां आप डेबिट कार्ड लगा कर, क्रेडिट कार्ड लगा कर, एटीएम कार्ड लगा कर पैसा निकालते हैं, उसमें भी नकली नोट निकले। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब कच्ची धानी से ही नकली तेल निकलने लगे और ट्रेजरी से ही नकली नोट निकलने लगे, तो हम किस पर विश्वास करें। कल अगर हम पोस्ट ऑफिस जाएं और वहां से नकली स्टाम्प निकले, तो क्या होगा! रेवेन्यू स्टाम्प पेपर, जो कचहरियों में मिलता है, जब स्टाम्प वेंडर से हमें नकली स्टाम्प मिले, तो तेलगी स्कैम खुला सामने आया। अब ये नकली नोट निकल रहे हैं और एक आकलन के हिसाब से, क्योंकि सरकारी आकलन तो वही है कि जो बैंक की खिड़की पर पकड़ा गया, उसी को नकली नोट माना जा रहा है, पर एक आकलन कह रहा है कि एक हजार, पांच सौ और सौ के जितने नोट हैं, उनके 50 फीसदी नोट नकली हैं, जो बाजार में हैं।